आप का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं ।

आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि अभी पिछली मर्तबा जो सारे देश में हड़ताल हुई थी उस में जिन लोगों ने भाग लिया था यह तो सही है कि किसी वैर भाव और बदले की भावना से उन के साथ न पेश आया जाय लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि आप को अनुशासन कायम रखना चाहिये और इस नाते जिनका दोष हो उन को माकूल दंड मिलना ही चाहिये अन्यथा अनुशासन कायम नहीं रह सकेगा। खास कर जो रिंगलीडर्स हैं उन के बारे में प्रशासन को ढिलाई नहीं करनी चाहिये और उन को सजा मिलनी ही चाहिये । जिन्हों ने अनुशासन भंग किया है उन के खिलाफ जो आवश्यक कदम अर्थात् डिसिप्लनरी ऐक्शन लिया जाना चाहिये वे लेना ही चाहिये ताकि भविष्य में अनुशासन भंग करने की हिम्मत न पड़े । यह जो समय मुझे दिया गया उस के लिये धन्यवाद ।

श्रीमती कृष्णा महता : (जम्मू तथा काश्मीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेलवे मंत्री तथा रेलवे बोर्ड को उन सफलताओं के लिये जो कि उन को रेलवे के प्रशासन में और रेलवे के काम में मिली हैं, बधाई देती हूं .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या कल को अपना भाषण जारी रक्खें ।

16.58 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION *RE.* ADIVASIS

Mr. Speaker: The House will now take up Half an Hour discussion. Shri Prakash Vir Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान का निर्माण करते समय जहां देश के ३४ करोड़ अन्य नागरिकों की सुविधा के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थायें की गई थीं वहां भारत के उन २ करोड़ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी जो आदिवासी क्षेत्रों में और विशेष कर जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं हमारे संविधान में धारा ३३८, ३३९ और ३४० के द्वारा राष्ट्रपति जी को यह अधिकार दिया गया था कि वह उन के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में कुछ विचार करें ।

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जी को यह अधिकार भी दिया गया था कि दस वर्षों के अन्दर किसी इस प्रकार की कमीशन की नियुक्तियां करें कि जिस कमीशन के द्वारा इन आदिवासियों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में विशेष रूप से जानकारी ली जा सके । भारतीय संविधान के लाग होने के कुछ समय के पश्चात् जून, सन १९५२ में अनुसूचित जातियों का एक सम्मेलन यहां दिल्ली के अन्दर हुआ था । इस सम्मेलन में महामान्य राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी आदि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्मिलित हुए । प्रधान मंत्री जी ने इस सम्मेलन में अपना वक्तव्य देते हुए जहां और बहुत सी बातें कहीं विशेष रूप से एक बात उन्हों ने यह कही थी :—

"वास्तव में, मुझे इस में सन्देह नहीं कि यदि साधारण तरीकों पर चला गया तो बाहरी अवाछनीय व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेंगे । वे जंगलों को अपने अधिकार में ले लेंगे और आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर देंगे । हमें उन के क्षेत्रों में इतनी सुरक्षा की व्यवस्था तो अवश्य ही करनी चाहिये कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उन की भूमि अथवा जंगलों पर अपना अधिकार न कर सके और बिना उन की मरजी और सद्भावना के उन के जीवन अथवा मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सके ।"

जहां प्रधान मंत्री जी ने इस सम्मेलन में अपनी यह सम्पत्ति दी थी वहीं राष्ट्रपति जी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

ने अपना वक्तव्य देते हुए इन आदिवासियों के सम्बन्ध में यह कहा था :—

"संसार के विभिन्न देशों के ईसाई मिशनिरियों ने उन में काफी काम किया है और बड़े त्याग से उन में शिक्षा का प्रसार किया है और उन की रहन सहन की हालतों में भी सुधार करने में साधारणतया सहायता की है। वे लोग अच्छी संख्या में उन्हें ईसाई बनाने में कामयाब हुए हैं।"

"मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि किसी विशिष्ट वर्ग धर्म अथवा अन्य समूह में उन्हें मिला देने के किसी भी विचार से प्रभावित न हो कर उन की सेवा की जाये।"

मैं यह बात इस दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं कि आदिवासियों को जो विधा आर्थिक तदृष्टि से केन्द्र की ओर से दी जाती है चाहे देखने में यह आया है कि वह उन्हें पूरी नहीं मिल पाती। अभी पीछे राष्ट्रपति जी की ओर से जो आयोग नियुक्त किया गया था श्री ढ़ेबर भाई की अध्यक्षता में यह आयोग अपना दौरा करने के लिये रांची के क्षेत्र में जब गया तो वहां के १२ हजार आदिवासियों ने हस्ताक्षर कर के श्री ढ़ेबर भाई को एक स्मरण पत्र दिया। पिछड़ी जाति सेवा संघ के मंत्री श्री ओम प्रकाश त्यागी और दया नन्द साल्वेशन मिशन के मंत्री श्री हरिश्चन्द्र विद्यार्थी ने मेरे पास यह समाचार वहां से भेजा कि श्री ढ़ेबर भाई से जब उन व्यक्तियों ने यह कहा कि आप आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से हम को उन्नत करना चाहते हैं परन्तु साथ ही यह तो देखिये कि हमारे सामाजिक जीवन में दूसरे व्यक्ति भी प्रवेश कर रहे या नहीं। श्री ढ़ेबर ने इस का उत्तर यह दिया कि हमें जो काम सौंपा गया है उस में यह काम नहीं आता कि हम इस दृष्टि से भी आप के सम्बन्ध में विचार करें कि सामाजिक दृष्टि से आप में किस प्रकार के परिवर्तन किये जा रहे हैं।

17.00 hrs.

[SHRI MULCHAND DUBE *in the Chair*]

प्रधान मंत्री जी ने उसी सम्मेलन में चिंता करते हुये यह बात भी कही थी कि ईसाई-धर्म-प्रचारकों ने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है और मैं भी उन का प्रशंसक हूं, परन्तु राजनैतिक दृष्टि से वे भारत में होने वाले परिवर्तनों के पक्ष में नहीं हैं। सच पूछिये तो जिस समय भारत वर्ष में नई राजनैतिक जाग्रिति का उदय हुआ, उस समय उत्तर-पूर्वी भारत में एक आंदोलन के द्वारा उत्तर-पूर्व भारत के निवासियों को अलग और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। इस में कोई संदेह नहीं कि इन आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई प्रचारकों ने बाहर से आकर शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक दृष्टि से उनको ऊंचा उठाने का पर्याप्त प्रयत्न किया, लेकिन उसके साथ ही साथ आज वहां पर स्थिति यह है कि केन्द्र से उन के लिये जो सुविधायें दी जाती हैं, उनका अधिकांश लाभ दूसरे रूप में उठाया जा रहा है। मेरे पास उसके कुछ आंकड़े हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियों के रूप में १९५१–५२ में २,८२ हजार, १९५५–५६ में १३,०५ हजार, १९५६–५७ में १५,७८ हजार, १९५७–५८ में १८,९७ हजार और १९५८–५९ में २०,७६ हजार रुपये दिये गये। किन्तु प्रश्न तो यह है कि ये छात्रवृत्तियां वहां के मूल आदि वासियों को कहां तक पहुंचती हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक ही उदाहरण प्रस्तुत करता हूं।

१९५६–५७ के आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकेंगे कि किस प्रकार इन छात्र-वृत्तियों का उपयोग हो रहा है। छोटा नागपुर के ला कालेज में १४ छात्रवृत्तियों में से १३ छात्रवृत्तियां ईसाई छात्रों ने ले लीं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग केन्द्र, टेक्निकल स्कूल में दोनों की दोनों छात्रवृत्तियां ईसाई छात्रों को मिल गई। एग्रीकल्चर कालेज

में दो से एक छात्रवृत्ति ईसाई को मिली। रांची स्कूल आफ इंजीनियरिंग में १२ में से ११ छात्रवृत्तियां ईसाइयों को मिलीं। रांची विमेंज कालेज में ४४६ छात्रवृत्तियों में से ४३८ छात्रवृत्तियां ईसाइयों को मिली। इसी तरीके से और भी बहुत से आंकड़े हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार आदिवासियों को उठाना चाहती है और इस सम्बन्ध में इतनी सद्भावना के साथ कार्य कर रही है, तो उसको यह देखना चाहिये कि यहां से जो आर्थिक सहायता वहां पहुंच रही है, वह मूल आदिवासियों तक जा रही है, अथवा नहीं, अथवा बीच में ही चतुर चालाक आदमी उसका उपयोग मूल अदिवासियों के लिये न कर के अपनी उन्नति के लिये कर लेते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर शिक्षा का अधिकांश कार्य ईसाई पादरियों द्वारा किया जा रहा है। प्रत्यक्षतः देखने में स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वे कहते होंगे कि हमारी संस्था में अमुक वर्ग के ऊपर प्रतिबन्ध है, या अमुक वर्ग को आने की छूट दी हुई है, किन्तु वहां जो व्यवहार किया जाता है, उसका परिणाम यह है कि जो छात्र प्राइमरी स्कूलों में प्रविष्ट होते हैं, धीरे धीरे उनकी मनोवृत्ति ईसाइयत की ओर ले जाई जाती है और पांचवी क्लास के बाद जब वे दूसरे स्तर पर आते हैं, तो उन्ही विद्यार्थियों को सुविधायें दी जाती हैं, जो या तो ईसाई हो चुके हैं, या ईसाई होने के लिये तैयार हैं। इस के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के लिये जो आवेदन पत्र आते हैं, वे भी उन्ही शिक्षा संस्थाओं के द्वारा आते हैं। इसका परिणाम यह है कि मूल अदिवासियों तक, जिनके लिये राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी इतने चिन्तित हैं, यह आर्थिक सहायता नहीं पहुंच पाती है। सरकार इस बात का पता लगाये कि कालेज स्तर पर जो छात्रवृत्तियां आदिवासियों को दी जा रहीं हैं, उनमें से कितनी मूल आदिवसियों को मिल रही हैं और कितनी धर्म-परिवर्तित आदिवासी ईसाइयों को मिल रही हैं। इसी तरह से इस बात का भी पता लगाया जाये कि विदेशों में शिक्षण के लिये जो छात्रवृत्तियों दी जा रही है, उन में क्रिस्चियन छात्रों को कितनी मिली हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वैसे मैं साधारणतया शिक्षा के राष्ट्रीय करण के पक्ष में कभी नहीं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति को देखते हुये वहां प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा का राष्ट्रीय करण कर दिया जाये। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो आदिवासी अपने बच्चों को ईसाई हो जाने के भय से ईसाइयों के स्कूलों में नहीं भेजते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकेंगे और उनके मस्तिष्क का यह भय दूर हो जायेगा।

सरकार की ओर से यह भी निश्चय किया गया है कि आदिवासियों को अधिक से अधिक नौकरियां दी जायें, लेकिन उसको यह ज्ञात होना चाहिये कि इस सम्बन्ध में विज्ञापन ऐसे पत्रों में प्रकाशित होते हैं, जो छोटे छोटे गांवों और देहातों तक नहीं जाते हैं। इसका परिणाम क्या है? जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने नागालैंड की चर्चा के समय कहा था, उन क्षेत्रों में जो ईसाई हो चुके हैं, वहां की लीडरशिप उन के हाथ में हैं और उन्होंने वहां अपने सर्विस ब्यूरो वगैरह बनाये हुय हैं। पहले से ही उन बच्चों की लिस्ट उनके पास रहती है, जो कि क्रिस्चियन हो चुके हैं। वे उनके ही आवेदन पत्र भिजवा देते हैं और मूल आदिवासी इन नौकरियों से भी वंचित रह जाते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में भी कोई उपाय सोचना चाहिय। या तो गांव की पंचायतों के पंचों के द्वारा यह काम किया जाय, या सरकार की जो इतनी विस्तृत मशीनरी है, वह एसी योजना बनाये कि उन क्षत्रों में मूल आदिवासी नौकरियों से पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। सम्भव है कि मेरे इस कथन में सन्देह किया जाय। इसका निराकरण करने के लिये मैं अपनी पुष्टि में यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात् आदिवासियों को जो नौकरियां

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

मिली हैं, उनमें यह टटोल कर देखा जाय कि उनमें से मूल आदिवासी कितने हैं, जो नौकरियों में जा सके हैं और कितने इस प्रकार के हैं, जो धर्म-परिवर्तित व्यक्ति हैं ।

सरकार की सुविधा और आदिवासी क्षेत्रों के हित की भावना से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वास्तविकता यह है कि आदिवासियों के नाम पर नकली आदिवासी पूरी सहायता को हड़प लेते हैं । होना यह चाहिये कि सरकारी मशीनरी को इस प्रकार का आदेश दिया जाये कि आर्थिक , सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से जो लोग इतने उन्नत हो चुके हैं कि उन को इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, उन को धीरे धीरे उस स्तर से निकालत रहना चाहिये और बाकी को सुविधा दी जाये । ट्राइबल वैलफेयर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने भी इस सम्बन्ध में सिफारिश करते हुये यह कहा था कि अगर सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता उन लोगों को भी मिलती रहे, जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से उन्नत हो चुके हैं, जो आगे बढ़े हुये हैं और चतुर चालाक भी हैं, तो सारी सहायता उन्हीं में सिमट कर रह जायेगी और बहुत पिछड़े हुये लोगों तक नहीं पहुंच पायेगी । इसका यह भी नुकसान होगा कि वे लोग इस सहायता को अपना अधिकार मान बैठेंगे और जिस दिन वह बन्द की जायेगी, वे इस के लिये संघर्ष और अन्दोलन करेंगे । अगर इस बात का पता लगा लिया जाये कि खास तौर से बड़े शहरों के आस पास जो आदिवासी हैं, वे इतने उन्नत हो चुके हैं कि उनको सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो इस से लाभ यह होगा कि उन से जो सहायता बच जायेगी, वह उन क्षेत्रों को दी जा सकेगी, जो बिल्कुल इन्टीरियर से हैं और जिन को इन दस वर्षों में सरकारी सहायता नहीं पहुंच पाई है ।

जहां तक विकास-खंडों का सम्बन्ध है, वहां अब तक स्थिति यह है कि पहले से उन्नत क्षेत्रों में नये नये विकास-खंड खुलते जा रहे हैं, जिस का परिणाम यह है कि विकास-अधिकारियों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और वे सरकार को दिखा देते हैं कि हम ने यहां विकास-खंड स्थापित करके इतना बड़ा काम कर दिया है । होना यह चाहिये कि जो बहुत पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, पहले से उन्नत नहीं हैं, विकास-खंड उन में स्थापित किये जाये, ताकि वे वहां पर उपयोगी सिद्ध हो सकें ।

आदि वासियों की परिभाषा के सम्बन्ध में भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाये और कुछ किया जाये, या न किया जाये, इतना तो अवश्य किया जाये कि जो आदिवासी स्वयं पढ़े हुये हैं, जिनकी अगली पीढ़ी भी पूरी तरह शिक्षित है, तो शिक्षा की दृष्टि से उस को आदिवासियों से अलग किया जा सकता है । या जिस आदिवासी की आय दो, ढाई या तीन हजार रुपये वार्षिक है, तो उसको कम से कम आर्थिक दृष्टि से पृथक किया जा सकता है । जिनकी आय भी अधिक है, जो शिक्षा की दृष्टि से भी आगे हैं, फिर भी अगर वे आदिवासियों के नाम पर दी जाने वाली सुविधाओं को लें, तो यह उन सुविधाओं का दुरुपयोग होगा ।

श्री ढेबर भाई के कमीशन को बारह हजार हस्ताक्षर उस क्षेत्र के निवासियों ने दिये थे । विशेष कर उस क्षेत्र की दस प्रमुख जातियों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर कर के दिये थे मेरे पास उस क्षेत्र के दस हजार हस्ताक्षर और और आये हैं । मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि मैं आपकी सेवा में उपस्थिति हो कर इन दस हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर देना चाहता हूं, ताकि आप को पता लग सके कि आप की ओर से जो सहायता उन लोगों को दी जाती है, वह पूरी उन तक पहुंच रही है या नहीं । राष्ट्रपति जी ने कहा है कि ६ मार्च

को वे हस्ताक्षर मैं दूं। इस सदन में मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि जिन लोगों के लिये यह सहायता नियत की गई है, वह उन को पूरी नहीं मिल रही है, जिस के परिणाम-स्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई है। इस लिये अच्छा यह होगा कि वातावरण को बिगड़ने से बचाने के लिये सरकार बुद्धि-मत्ता से काम ले और इस बात की व्यवस्था करे कि वह सहायता जिन को दी जानी चाहिये और जो उसके वास्तविक अधिकारी हैं उन्हीं तक वह सहायता पहुंच सके, यह मेरा नम्र निवेदन है।

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch. Tribes): I am very glad that considerable interest appears to be taken about a section of the Adibasi community that has been neglected by everybody and not only by Government.

My hon. friend from Gurgaon has been taking a lot about Jharkhand, Chota Nagpur and so on. I really do not know how much he knows about it. It happens to be my constituency, and I would like to tell him that I am a member of the Dhebar Commission. It is my own district and I would advise him not to put too much emphasis on the number of signatories one can collect. For every one he can collect I might be able to collect a thousand. That is no argument at all. Every time there has been a Minority Sub-Committee—it was in the Constituent Assembly days when I was also a member with Thakkar Bapa—the same thing happened. *Ad hoc* bodies spring up here and there with a particular slant.

There is no doubt whatever, and it is something I have been trying to stress all the time in this House and elsewhere—about what he calls *mool* Adibasi. Then he discovered a *nakli* Adibasi. About twenty years ago there were *Sanatan* Adibasis and some other Adibasis. If you go to Santhal Parganas, there our friends have discovered another expression, *Sapha* or clean Santhal and unclean Santhal. All these expressions mean nothing. We have thrashed this out during the days of the Constituent Assembly—the attempt to make a bifurcation on religious basis. My friends have already lost the battle and they will continue to lose it. Now they had better think of our present pattern, a determined pattern where the economic conditions shall not be prejudiced by any religious considerations.

Now, here is a case—and he is quite quight—where because of my own friends, and their ancestors, their neglect of them, their tyranny of them—by the zamindars and so forth—a certain element came into that area, looked after these people, gave them a little bit of education, not very much. But anyhow there was somebody to look after these people. People were tyrannized, and to this day they are being tyrannized. Well, I have always been against proselytisation. It is something I can take credit to myself, I have stopped it. Because, I do not believe in any religious body, does not matter what it is, whether it is of this country or of some other country, taking unfair advantage of a man who is hungry, who changes his religious loyalty for the sake of a little bit of help he may get here and there.

But the point is this. The Government, not only in Bihar but everywhere else, has failed to reach these people who have not been reached by the missionaries. That is a fact. They have been completely neglected.

Now, my hon. friend, the hon. Member from Gurgaon, has been talking of these scholarships going to the wrong places. The scholarships cannot reach, because they have never taken to education—that is the trouble—not because others who had an earlier start are able to take advantage of it. The fact is that people did not even get a start.

[Shri Jaipal Singh]

I am very sorry that the name of Dr. Rajendra Prasad should have been brought into this picture But since it has been brought in, I think in fairness to him I should present the correct picture about his endeavours in this particular regard. He started the Adimjati Sewak Sangh. The whole idea was that there was this one section that had been so neglected that should be served. But who are the people serving them? Mr. Narayanji, getting lakhs and lakhs of rupees. This very Mr. Narayanji was the man who collected ten thousand and twelve thousand signatories. Who is he? Have the accounts ever been audited? (*Interruption*). A welfare worker who, because he is a welfare worker, becomes a very rich proprietor in my home district—these are the types of people who are doing disservice to the real cause.

But I am very glad about my hon. friend that he should have drawn the attention of this House and, through what he has said here, of the outside world in India also that we must not merely think of what we are doing in these urban areas. In the urban areas everywhere, does not matter which community it is, it is the urban people who can take advantage of things. What is happening in the rural areas? Why do you talk of these poor Adibasis? Do you know their language? Do you sit and eat and drink with them? You know nothing about them. It is your venom against something from outside. Not that you have done anything for them. Have you cut a blade of grass to feed them? What is the good of talking like this, Nagaland, Jharkhand this and that. Please come along and serve them; you are welcome.

The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva): Mr. Chairman, Shri Prakash Vir Shastri has spoken with deep feeling about the condition of the Adivasis and pinpointed mainly Chotanagpur. Shri Jaipal Singh has more or less answered his points. Today, I want to pinpoint this. What he wanted to say is that the Christian missionaries are in complicity with government officials and certain things go wrong and certain scholarships are carried away by those more fortunate who, naturally are Christians in this particular area.

What today we must understand is that there are different categories of Adivasis and as Shri Jaipal Singh has pointed out, there are more progressives sections and weaker sections within the Adivasis. There was a time in the pre-Indepenence era when we talked of conversion *en masse*. That era is over. Mass conversion is completely out of date. Nobody talks of conversion in that sense. What happens to those who are Christians already? Shri Prakash Vir Shastri said that event others come under the influence of the Christian missionaries and they get converted or they are prepared from the primary school stage to the higher stages for conversion. I do not think that should be true. Though I am a Christian, I do not subscribe to the view that conversion should be done in that manner. I would call it not conversion, but perversion. Because, in free India, each individual should be left to himself to decide what he wants to be and he should do so only when he has reached an age of reasoning and thinking correctly for himself.

He mentioned that certain facts were given to Dhebarbhai. But this discussion arises out of an unstarred question that I answered in the month of December in which the hon. Member had asked, whether we had received any memorandum. We have received a memorandum. But, that has been refuted by the other hon. Member. Signatures do not count, and especially when the signatures are not even written but printed, we cannot substantiate that. Therefore, I would call this charge that has been made on the floor of the House rather fantastic. More than that, I could not

say. It is more than far-fetched. We must know that within the Adivasis, there is the lower income group, there is the higher income group, there are weaker sections and there are those who have been educated. Those who have been educated are naturally Christians in some of these thick-thickly populated areas from which Adivasis come. It is true that when scholarships are announced, those who have been educated up to a certain level will come forward and take them. Today, we are thinking of the economic conditions of the Adivasis in general terms. I want to bring to the notice of the hon. Member that for even 5 per cent of the posts that we have reserved for the Adivasis, people are not forthcoming I do not know how you can say that this sort of discriminatory attitude is seen anywhere because, for even 5 per cent we have not got people.

Another charge that Shri Prakash Vir Shastri made is that there may be a collusion between the missionaries and government officers. The government officers are by and large non-Christians. We have so many methods by which we get progress reports from all the areas where the Adivasis live, following their avocation, education of children and education of grown up students. We have got a Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The report comes before you. All the details are placed before the House. I do not think that the missionaries are taking undue advantage. I would like the hon. Member to give me individual instances where the missionaries have over-stepped their bounds. I can assure the hon. Member that we shall look into them very carefully and if need be, tage action. I need not re-emphasise that the days of conversion as we had understood in the pre-Independence days are over. Shri Jaipal Singh has also emphasised that particular point.

It is also true that the Advasis lost themselves in the mountain region because they were gradually driven out of the urban or civilised areas, where educated men or men of status do not reach them to give them any assistance.

I shall briefly refer to the funds for the welfare of the Scheduled Tribes. Certain specified funds are provided for the welfare of the Scheduled Tribes, which are intended for certain specific and approved schemes and the progress reports which are received periodically from the field enable not only us but the State Governments and the Union Territories also to ensure that the funds are spend properly on approved and specified schemes. If Shri Prakash Vir Shastri can specifically point out that something is going wrong in any region, we can enquire into it. He has pointed that in the Nagpur region the Christians missionaries have taken over certain institutions or hostels—I may not have understood him correctly—but if he really gives specific instance, we shall look into them and see why they have taken over, whether they have been handed over to them for running them well, or whether they have snatched them away in a wrong way; and if it is in a wrong way, we shall certainly take action.

It was asked whether the Government had receieved complaints. Government receive complaints from time to time. I have said that we did receive a complaint, but it was of such a nature that we could not even begin the examination, because, when a complaint comes in a printed form sometimes, without even one signature, we do not know how to substantiate it. Nevertheless, we examined it thoroughly in the Ministry. We have got different advisory boards, different committees, we have the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we have got very many agencies through which we examine every one of the complaints that comes before us.

[Shrimati Alva]

I may also point out to Shri Prakash Vir Shastri that where one talks of Adivasis, one has to bear in mind that religion is not a factor to be taken into consideration. I want to reiterate this, that in the case of a Scheduled Casts person being converted, he loses his caste, but in the case of the Adivasi, he remains an Adivasi, whether he is a Budhist, or whether he becomes a Christian or a Muslim he remains an Adivasi. Therefore, religion does not matter in the case of Adivasis. It is only discrimination that may be exercised by individuals. He alleged that the educated ones are able to take away the scholarships and other advantages and privileges from the weaker sections of the Adivasis. That surely we must look into, and that is being done from time to time.

There is nothing more to say except that the suggestion that Shri Prakash Vir Shastri has made in this half-hour discussion cannot be accepted As I said, it is very fantastic. Only if he comes down to brass tacks and gives us absolutely case by case where this sort of discrimination has led to injustice, can we substantiate and go into it and give him an answer.

That is all I have to say.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

PRESENTATION OF SEVENTY-SEVENTH REPORT

Shri Jhulan Sinha (Siwan): I beg to present the Seventy-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

17.24 hrs.

The Lok Sabha then adjorned till Eleven of the Clock on Thursday, March 2, 1961/Phalguna 11, 1882 (Saka)